नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 106
दि. 14.08.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे

एक भव्य आयोजन समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त नए भारत की झलक पेश करेगा

(जीएनएस)।

राष्ट्र 15 अगस्त 2025 को अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री इस प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएँगे और संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसे में जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय "नया भारत" रखा गया है। यह समारोह एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त नए भारत के लगातार विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करने के एक मंच के तौर पर काम करेगा।

समारोह लाल किले पर आगमन के साथ, प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह करेंगे। रक्षा सचिव, दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का प्रधानमंत्री से परिचय कराएँगे। इसके बाद, दिल्ली क्षेत्र के जीओसी, श्री नरेंद्र मोदी को सलामी मंच तक ले जाएँगे, जहाँ अंतर-सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड की संयुक्त टुकड़ी, प्रधानमंत्री को सलामी देगी। इसके बाद, प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे।

प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते में 96 जवान शामिल होंगे (एक अधिकारी और सेना, नौसेना, वायु सेना और दिल्ली पुलिस, प्रत्येक से 24 जवान।

भारतीय वायु सेना इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का समन्वय कर रही है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर ए एस सेखों संभालेंगे।

प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना दस्ते की कमान मेजर अर्जुन सिंह, नौसेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर कोमलदीप सिंह और वायु सेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा संभालेंगे। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान अतिरिक्त डीसीपी श्री रोहित राजबीर सिंह के हाथ में होगी।

मुख्यमंत्री ने 'हर घर तिरंगा अभियान' का शुभारम्भ किया

प्रधानमंत्री जी के विकसित व आत्मनिर्भर भारत विजन से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमें विकसित व आत्मनिर्भर उ0प्र0 के विजन को अपने जीवन का मंत्र बनाना होगा : मुख्यमंत्री

तिरंगा यात्रा हमें भारत माता, भारतीय महापुरुषों व वीर क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करती

देश व प्रदेश के प्रत्येक घर में भारत की आन-बान-शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाना चाहिए

निजी स्वार्थ की तिलांजलि देकर प्रत्येक परिस्थिति में देश के सम्मान को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का दायित्व

लखनऊ : 13 अगस्त, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित व आत्मनिर्भर भारत विजन से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमें विकसित व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को अपने जीवन का मंत्र बनाना होगा।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर 'हर घर तिरंगा अभियान' (13 से 15 अगस्त, 2025) का शुभारम्भ करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज 'हर घर तिरंगा अभियान' का शुभारम्भ किया जा रहा है। हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है। आजादी के अमृतकाल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, महान क्रान्तिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तिरंगा यात्रा हमें भारत माता, भारतीय महापुरुषों व वीर क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करती है। देश व प्रदेश के प्रत्येक घर में भारत की आन-बान-शान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाना चाहिए।

यह हमारे देश व सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। सभी प्रदेशवासी राष्ट्र माता के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए तिरंगे को प्रत्येक घर में लगाकर देश की आजादी के 78 वर्षों के शानदार समारोह में सम्मिलित हों।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को दुनिया ने देखा है। भारत की शक्ति और सामर्थ्य देखकर पूरी दुनिया अचम्भित है। अपने निजी स्वार्थ की तिलांजलि देकर प्रत्येक परिस्थिति में देश के सम्मान को बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का दायित्व है। क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब तथा सम्प्रदाय आदि के नाम पर देश को बांटने वाले तत्वों को बेनकाब करना अत्यन्त आवश्यक है।

210 पंचायत प्रतिनिधि विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे

79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एआई संचालित टूल "सभासार" का शुभारंभ होगा तथा पंचायत प्रतिनिधिओं को सम्मानित किया जाएगा

(जीएनएस)।

पंचायती राज मंत्रालय 15 अगस्त को नई दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 210 पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में मेजबानी करेगा। अपने जीवनसाथी और नोडल अधिकारियों के साथ, कुल 425 प्रतिभागी इस समारोह में शामिल होंगे।

इन विशिष्ट अतिथियों के लिए 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक औपचारिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर

पर उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय "आत्मनिर्भर पंचायत, विकसित भारत की पहचान" है, जो विकसित भारत के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में आत्मनिर्भर पंचायतों के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस सम्मान समारोह के दौरान एआई संचालित 'सभासार' एप्लिकेशन का शुभारंभ होगा और 'ग्रामोदय संकल्प पत्रिका' के 16वें अंक का भी विमोचन होगा।

इस वर्ष के विशेष अतिथियों में बड़ी संख्या में महिला पंचायत प्रतिनिधि शामिल हैं, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और समावेशी सामुदायिक पहल जैसे प्रत्यक्ष सुधार लाए हैं। पंचायती राज संस्थाओं की ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ग्रामीण नेतृत्व की उभरती हुई शक्ति का उदाहरण हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शासन संबंधी ज़िम्मेदारियों को दूरदर्शी विकास दृष्टिकोणों के साथ सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। इन्होंने हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मिशन इंद्रधनुष जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं को साकार कराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है और साथ ही जमीनी स्तर पर नवीन स्थानीय पहलों व समाधानों को प्रोत्साहित भी किया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 1.47 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी, स्वीकृत घरों की कुल संख्या 8.56 लाख हुई

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

सभी के लिए आवास' (एचएफए) के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 1.47 लाख अतिरिक्त पक्के मकानों को मंजूरी दी है। इस नवीनतम मंजूरी के साथ, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 8.56 लाख हो गई है। यह निर्णय 12 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित जीपीओए-2 में श्री श्रीनिवास कटिकिथला, सचिव, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की चौथी बैठक के दौरान लिया गया। कस्तूरबा गांधी मार्ग कार्यालय में आयोजित यह सभी के लिए आवास (एचएफए) प्रभाग की पहली बैठक थी।

बैठक में संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (संयुक्त परामर्श एवं प्रबंध निदेशक) श्री कुलदीप नारायण, आवास वित्त मंत्रालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पीएमएवाई-यू मिशन निदेशक और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुल 1,46,582 घरों को मंजूरी दी गई है।

स्वीकृत आवास, शहरी गरीबों की आवासीय जरूरतों को पूरा करेंगे और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से युक्त किफायती और सम्मानजनक पक्के मकान उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। यह निर्णय शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है।

बैठक को संबोधित करते हुए, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवास परियोजनाओं को बुनियादी ढांचे के गलियारे के साथ जोड़ने पर जोर देने का आग्रह किया।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने कहा, "राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक रूप से योजना बनानी चाहिए और आवास परियोजनाओं को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करना चाहिए जहां बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि और सेवाओं तक बेहतर पहुंच हो।"

एचएफए के संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव को पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया और कहा कि बड़े राज्यों, विशेष रूप से मेट्रो शहरों को योजना के साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) खंड पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसएमसी के लिए प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके तहत समूह आवास परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है।

इन योजनाओं के तहत 120 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 93.81 लाख पक्के घर पहले ही बनकर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य के अनुरूप, इस योजना को नया रूप दिया गया और सितंबर 2024 में इसे पीएमएवाई-यू 2.0के रूप में लॉन्च किया गया। एक करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को शहरों में पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के साथ-साथ एमआईजी परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, पीएमएवाई-यू 2.0के तहत लाभ के पात्र हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 को चार कार्यक्षेत्रों यानि लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास, किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। सीएसएमसी बैठक में स्वीकृत आवास योजना के बीएलसी और एएचपी वर्टिकल के अंतर्गत हैं।

राज ठाकरे की एमएनएस ने निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया दिवाली के बाद शुरू होने की उम्मीद है। चंद दिन पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने यह जानकारी दी थी। जिसके बाद सभी राजनीतिक दल चुनाव की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने आगामी निकाय चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की विपक्षी दलों की मांग का समर्थन किया है। राज ठाकरे की मनसे के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और अपनी मांगों की सूची सौंपी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) के उपयोग पर जोर दिया गया।

जेपी सेनानियों के सम्मान में ऐतिहासिक निर्णय, पेंशन दोगुनी, 1 अगस्त 2025 से लागू- सम्राट चौधरी

(जीएनएस)।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की सलाखों के पीछे सालों तक संघर्ष करने वाले जेपी आंदोलन के सेनानियों के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। बिहार कैबिनेट ने उनके सम्मान पेंशन को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर न केवल एक आर्थिक राहत दी है, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दिया है।

समाज के असली नायकों का सम्मान केवल भाषणों में नहीं, बल्कि ठोस कदमों से होना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक चले आंदोलन में मीसा या डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे सेनानियों को अब पहले से दोगुना पेंशन मिलेगा।

1 माह से 6 माह तक जेल में रहने वालों की पेंशन 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और 6 माह से अधिक जेल में रहने वालों की पेंशन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, और पेंशनधारी के निधन के बाद उनके जीवित पति/पत्नी को भी इसी दर से पेंशन मिलेगी।

यह निर्णय केवल आर्थिक सहायता भर नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी के त्याग को स्मरण करने का अवसर है, जिसने लोकतंत्र बचाने के लिए अपने जीवन के सुनहरे वर्ष जेल में गुजार दिए। ऐसे में एनडीए सरकार का यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि देश और राज्य के लिए किया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जाता।

राजनीति में बहुत बार घोषणाएं होती हैं, पर जब कोई सरकार पुराने संघर्षों के योद्धाओं को याद कर उन्हें उचित सम्मान देती है, तो यह उस शासन के संवेदनशील और जिम्मेदार चरित्र को दर्शाता है। जेपी सेनानियों के सम्मान में उठाया गया यह कदम बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल संसद और विधानसभाओं में नहीं, बल्कि उन लोगों में है, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और कीमत चुकाई।

बौद्धिक संपदा कार्यालय में विस्तारित क्षमता और आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आईएसए भवन का उद्घाटन

नवाचार संप्रभुता का प्रतीक है और भारत की वैश्विक प्रगति को गति देगा: श्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज द्वारका नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) के नव-विस्तारित आईएसए भवन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि नवाचार सदियों से भारत की पहचान का अभिन्न अंग रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। कोणार्क मंदिर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक संरचनाओं की सटीकता और इंजीनियरिंग, देश में हजारों वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही नवाचार की गहरी संस्कृति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नवाचार न केवल बौद्धिक संपदा का एक रूप है, बल्कि संप्रभुता का प्रतीक भी है, और यह भारत को विश्व में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री गोयल ने बताया कि प्रत्येक विकसित देश में नवाचार, नए विचार, अनुसंधान और विकास प्राथमिकता रहे हैं और इसी पर ध्यान केंद्रित करने से उनकी समृद्धि हुई है। मंत्री महोदय ने जोर देकर कहा कि देश का विकास नवाचार के कंधों पर टिका है और बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र को अब दुनिया भर में विकास के एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में मान्यता मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि सभी हितधारक अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करें, तो यह संस्थान 2047 तक विकसित भारत की ओर देश की यात्रा का केंद्र बन जाएगा और अनुसंधान एवं विकास के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करेगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रगति उल्लेखनीय है, बौद्धिक संपदा का विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर के लिए एक प्रतिभा केंद्र बन जाएगा।

यह उद्घाटन भारत के बौद्धिक संपदा ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक जाँच प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए, 2014 में एक आईएसए/आईपीईए भवन का निर्माण किया गया था, जिसमें भूतल और प्रथम तल शामिल हैं। भारतीय बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने 2018 में एक विस्तारित भवन के निर्माण को मंजूरी दी। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा शुरू की गई यह परियोजना 2025 में पूरी होनी थी।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण, आम जनता से रेल पटरी से दूर रहने की अपील

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित ब्रॉड गेज लाइन का निरीक्षण 14 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान इस सेक्शन पर तीव्र से ट्रेन चलाई जाएगी। अतः आम नागरिकों से विशेष अपील की जाती है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से रेल पटरी और इसके आसपास के क्षेत्रों से दूर रहें।

परियोजना का चरणबद्ध रूप से कमीशनिंग प्रस्तावित है:

- हिम्मतनगर से इडर (31 किमी) – वर्तमान चरण में खोलने का लक्ष्य
- इडर से खेड़ब्रह्मा (23.83 किमी) – सितंबर 2025 तक खोलने का लक्ष्य

"यह परिवर्तन केवल गेज में सुधार नहीं है; यह साबरकांठा क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी, अवसर और विकास क्षमता में भी सुधार है।"

इस निरीक्षण के पश्चात अंतिम स्वीकृति मिलने पर इस रेल खंड पर नियमित ट्रेन सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। इससे असारवा से खेड़ब्रह्मा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी, जिससे साबरकांठा सहित उत्तर गुजरात के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा।

इस गेज परिवर्तन परियोजना के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित उत्तर गुजरात के लोगों को अब बेहतर, तेज और सुरक्षित रेल सेवा प्राप्त होगी। इस मार्ग पर उन्नत संरचनाएं और आधुनिक सुरक्षा मानकों को अपनाया गया है, जिससे यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बन सकेगी।

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल द्वारा कीड्स हट एवं बाल मंदिर के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपीटिशन

'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO), भावनगर मंडल द्वारा संचालित कीड्स हट एवं बाल मंदिर के नन्हें – मुन्हें बच्चों के बीच ड्राइंग कंपीटिशन करवाया गया। सभी प्यारे प्यारे छोटे-छोटे बच्चों ने बहुत हीं सुंदर चित्र बनाए।

यह दोनों स्कूल 37 वर्षों से चलता आ रहा है। इस कंपीटिशन में सभी बच्चों ने बहुत हीं सुंदर चित्र बनाकर वहां उपस्थित पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWWO),

भावनगर मंडल की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी वर्मा एवं महिला कल्याण संगठन की सभी पदाधिकारियों का मन मोह लिया। इस दरमियान उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया।

'हर रेल घर तिरंगा' में 18,000 रेल परिवारजन की ऐतिहासिक भागीदारी – महिला कल्याण संगठन अहमदाबाद की अध्यक्षा शेफाली गुप्ता बनीं प्रेरणा स्त्रोत

अहमदाबाद, 13 अगस्त 2025 — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान को एक नई ऊर्जा देते हुए, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, (हफ्हहड) अहमदाबाद की अध्यक्षा श्रीमती शेफाली गुप्ता के नेतृत्व में न्यू रेलवे कॉलोनी, साबरमती में 'हर रेल घर तिरंगा' रैली का भव्य आयोजन हुआ।

इस आयोजन में 2000 से अधिक रेल परिवारजन शामिल हुए। रैली की शुरूआत सामुदायिक भवन, साबरमती से हुई और रेलवे कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए देशभक्ति के रंग में सराबोर वातावरण में 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारे गूंजते रहे।

कार्यक्रम में माननीय विधायक डॉ. हर्षदभाई पटेल ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर तिरंगा' आ'ान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है, और रेल परिवार इसका शानदार उदाहरण है।'

श्रीमती शेफाली गुप्ता, जो वर्षों से जनसेवा और सामुदायिक उत्थान में अग्रणी रही हैं, ने कहा — 'हर घर रेल तिरंगा, हर दिल में भारत – यही हमारे देशप्रेम की असली पहचान है।' उनकी प्रेरणा ने इस अभियान को केवल एक रैली नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय एकता के उत्सव में बदल दिया।

रैली के उपरांत 500 से अधिक घरों में कॉलोनीवासियों को तिरंगा वितरित किया गया, ताकि 15 अगस्त को हर घर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराए। अहमदाबाद मंडल द्वारा 14 अगस्त 2025 को मणिनगर और अन्य रेलवे कॉलोनियों में भी यही अभियान जारी रहेगा।

इस साल अहमदाबाद रेल मंडल के 18,000 से अधिक घरों में तिरंगा बाटने का प्लान है। साथ ही अहमदाबाद मंडल के अपने स्टाफ के बीच 'फोटो तिरंगा के साथ' फोटो कम्पटीशन भी रखा है, जिसमे रेलवे मेन को अपना फोटो तिरंगे के साथ खींच कर @ड्रस्टऑर्गि को टैग करना है और #ल्ं१फ्रं'ॠ१ळ१ंल्लॅ हैशटैग के साथ पोस्ट करना है। डिवीजन अच्छे फोटोग्राफ़्स को अवार्ड भी देगा।

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल ने एक बार फिर साबित किया कि वह देश की प्रगति के साथ-साथ सामाजिक एकजुटता और राष्ट्र निर्माण में भी सदैव अग्रणी है।

भारत में पारदर्शी और उत्तरदायी खाद्य सूचना पत्र लगाने के लिए रूपरेखा तैयार

एफएसएसएआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में भारत में पारदर्शी और उत्तरदायी खाद्य सूचना पत्र लगाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई; खाद्य सूचना पत्र लगाने और विज्ञापन में विश्वास तथा उत्तरदायित्व पर बल दिया गया

यह परामर्श वर्तमान नियमों की समीक्षा करता है, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करता है और उपभोक्ता संरक्षण, जन स्वास्थ्य तथा खाद्य उद्योग में नवाचार बढ़ाने के लिए वैश्विक मानकों के साथ संरेखण का प्रयास करता है

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने उभरते खाद्य क्षेत्र में नैतिक और सही सूचना पत्र तथा विज्ञापन की आवश्यकता पर बल दिया; सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, खाद्य उत्पादों की बारीकी से जाँच करने तथा ऐसे महत्वपूर्ण परामर्श आयोजित करने का आग्रह किया

खाद्य सूचना पत्र केवल एक विपणन उपकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे उत्पादक और उपभोक्ता के बीच विश्वास का सबसे आवश्यक कारक भी माना जाना चाहिए, हम खाद्य उत्पाद में शामिल सभी चीजों की सही और ईमानदार घोषणा चाहते हैं और अंतिम निर्णय उपभोक्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए: श्रीमती निधि खरे

श्री संजीव सान्याल ने विज्ञापनों में वैज्ञानिक दावों के बाहरी सत्यापन की आवश्यकता पर बल दिया; सूचना पत्र उद्योग के लिए अनिश्चितता को कम करने के लिए सूचना पत्र में सभी परिवर्तनों को वर्ष में एक बार लागू करने के एफएसएसएआई के निर्णय की प्रशंसा की

(जीएनएस)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में खाद्य सूचना पत्र, विज्ञापन और दावों पर भारत के नियामक ढांचे को मजबूत करने के एक मजबूत प्रयास के अंतर्गत, 'खाद्य सूचना पत्र, विज्ञापन और दावों पर नियामक ढांचे का व्यापक विश्लेषण' विषय पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस परामर्श में संबंधित मंत्रालयों, सरकारी विभागों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, खाद्य व्यवसायों, राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों, उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 700 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसका उद्देश्य वर्तमान नियमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने, जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने तथा खाद्य उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने के स्वरूप तलाशना था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव, श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने उद्घाटन भाषण में खाद्य क्षेत्र में सूचना पत्र और विज्ञापन में नैतिक तथा सत्यनिष्ठ प्रथाओं के महत्व पर बल दिया। श्रीमती श्रीवास्तव ने खाद्य क्षेत्र के विकसित होते माहौल की ओर इशारा करते हुए कहा, "आज चीजें तेजी से बदल रही हैं। अब हम पूरी दुनिया के संपर्क में हैं, जिसका अर्थ है कि हमें कई सकारात्मक बदलावों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना होगा, साथ ही खाद्य उत्पादों की और भी बारीकी से जाँच करनी होगी। इस तेजी से बदलती दुनिया में, इस तरह के परामर्श अत्यंत आवश्यक हैं।"

उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे ने खाद्य उद्योग में ईमानदार और सत्य घोषणाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उद्योग से सच्ची और ईमानदार घोषणाएँ करने, स्वेच्छा से यह बताने कि उत्पाद में क्या है और भ्रामक विज्ञापनों और छल-कपट से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि "खाद्य सूचना पत्र केवल एक विपणन उपकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे निमार्ता और उपभोक्ता के बीच विश्वास का सबसे आवश्यक कारक भी माना जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि खाद्य उत्पाद में जो कुछ भी शामिल है, उसकी सच्ची और ईमानदार घोषणा हो और अंतिम निर्णय उपभोक्ता पर छोड़ दिया जाना चाहिए।" उन्होंने यह सुनिश्चित करने के सामूहिक दायित्व पर भी बल दिया कि यह जानकारी सटीक, पारदर्शी और सत्य हो, ताकि उपभोक्ता पूर्ण विश्वास के साथ सूचित, सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प चुन सकें।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, श्री संजीव सान्याल ने उद्घाटन सत्र के दौरान अपने विशेष संबोधन में कहा, 'विज्ञापनों में दावों के मुद्दे की भी गहन जाँच की आवश्यकता है क्योंकि भले ही उनके समर्थन में कथित वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हों, फिर भी उन्हें बाहरी रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है।' इस संबंध में श्री सान्याल ने एफएसएसएआई के योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा, 'इस वर्ष की शुरूआत में एफएसएसएआई द्वारा एक घोषणा की गई थी कि सभी सूचना पत्र में परिवर्तन और संबंधित नियम तथा विनियम अब वर्ष में केवल एक बार, 1 जुलाई को लागू होंगे। यह वास्तव में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सूचना पत्र उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या और अनिश्चितता को दूर करता है।'

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री प्रभात ने खाद्य क्षेत्र में झूठे दावों की गंभीरता का उल्लेख करते हुए, उत्तरदायित्व और सटीक संचार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है कि विज्ञापन नैतिक, सत्य और भ्रामक न हों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दावों के संदर्भ में। इस क्षेत्र में झूठे दावे न केवल उपभोक्ता के भरोसे को कमजोर करते हैं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा भी पैदा करते हैं।"

केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक 19 अगस्त 2025 को होगी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समग्र स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 मई 2025 को एक अलग आयुष परामर्शदात्री समिति का गठन किया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय की नवगठित परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक 19 अगस्त 2025 (मंगलवार) को आयोजित होगी। यह बैठक मंत्रालय और सांसदों के बीच सार्थक संवाद को सरल बनाएगी, जिससे आयुष के क्षेत्र में प्रमुख पहलों और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा और परामर्श मुमकिन हो सकेगा। समिति की अध्यक्षता आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव करेंगे।

भारत सरकार ने, भारत के स्वास्थ्य सेवा ढांचे में आयुष प्रणालियों के बढ़ते महत्व को देखते हुए, 5 मई 2025 को आयुष मंत्रालय के लिए एक अलग परामर्शदात्री समिति का गठन किया है।

इससे पहले, आयुष मंत्रालय से संबंधित मामलों को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के अधीन देखा जाता था। आयुष के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति का गठन, आयुष संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित, संसदीय निगरानी और सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम संस्थागत कदम है।

आयुष मंत्रालय के लिए स्वतंत्र परामर्शदात्री समिति का गठन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और समग्र स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दशार्ता है। प्रधानमंत्री आयुष प्रणालियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करने और भारत के पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के महत्व पर लगातार जोर देते रहे हैं।

यह उपलब्धि आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निरंतर प्रयासों और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समन्वित कार्रवाई का नतीजा है, जिसने इस वर्ष की शुरूआत में समिति को अधिसूचित किया था।

मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण को आगे बढ़ाने और देश भर में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मकसद से, समिति के सदस्यों के साथ उपयोगी चर्चा की उम्मीद करता है।

आईबीसी 22 अगस्त 2025 को युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीवाईबीएस) आयोजित करेगा

(जीएनएस)।

धम्म का सार संरक्षित करने में युवाओं की भूमिका को मजबूत करने के अपने प्रयासों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी), नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025 को युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीवाईबीएस) आयोजित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के नालंदा हॉल में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

आईसीवाईबीएस ने अपने पिछले सम्मेलनों में जीवंत विषयों पर गहन चर्चा की है। 2023 में "बौद्ध तीर्थयात्रा" पर चर्चा से लेकर 2024 में "शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में बुद्ध धम्म" पर जोर देने तक, 2025 की विषय वस्तु का उद्देश्य "21वीं सदी में बुद्ध धम्म में ज्ञान संचार" पर चर्चा करना है।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह उपस्थित रहेंगे। मुख्य भाषण प्रख्यात बौद्ध इतिहासकार प्रो. केटीएस सराओ देंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की भूमिका को बार-बार "धम्म सेतु" के रूप में देखा है, जो एक आध्यात्मिक सेतु है जो न केवल बौद्ध-बहुल देशों को बल्कि पूरे विश्व को जोड़ता है। भारत को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन और पाली को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने जैसी पहलों के माध्यम से बुद्ध धम्म के संरक्षण में योगदान देने में अग्रणी होने पर गर्व है। "धम्म-आधारित सद्भाव" का सिद्धांत भारत के पंचामृत सिद्धांत में निहित पाँच स्तंभों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

इसलिए, यह सम्मेलन

निम्नलिखित पर गहन शोध करेगाः

धम्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने करुणा, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव पर आधारित समावेशिता के सिद्धांत पर आधारित एक विरासत छोड़ी है। पूरे भारत में प्रसारित अपने शिलालेखों के माध्यम से भावी पीढ़ियों को तैयार करने में सम्राट अशोक के प्रयासों के सम्मान में, इस संगोष्ठी का पहला विषय "बुद्ध धम्म के प्रसार में अशोक की भूमिका" पर चर्चा करना है। यह विषय वस्तु उनकी शिक्षाओं का विस्तार से अध्ययन करती है, जो श्रीलंका से हेलेनिस्टिक क्षेत्रों और मध्य एशिया तक फैली।

भारतीय परंपरा "गुरु-शिष्य" संबंध के महत्व के लिए जानी जाती है, जो ज्ञान हस्तांतरण का आधार है। दूसरा विषय "गुरु शिष्य परंपरा – बुद्ध धम्म में ज्ञान हस्तांतरण के मॉडल" पर चर्चा करेगा। गुरु केवल धम्म की व्याख्या ही नहीं करते, बल्कि अपने आचरण और जीवनशैली में परिलक्षित वास्तविक अभ्यासों के माध्यम से उसे साकार भी करते हैं। शिष्य केवल धम्म का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि उनकी भूमिका अध्ययन से भी आगे तक जाती है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के वाहक होते हैं। इसलिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है जिस पर आगे बढ़ना आवश्यक है।

बौद्ध धर्म आधुनिक तकनीक के साथ-साथ विकसित हो रहा है और अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए नए साधनों को अपना रहा है। जैसे-जैसे युवा पीढ़ी डिजिटल नवाचार की ओर आकर्षित हो रही है, वे धम्म से जुड़े रहने और उसकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम हैं। भारत में, केवल 30 प्रतिशत महिलाएं ही इंटरनेट का उपयोग करना जानती हैं, जबकि पुरुषों में यह दर 57 प्रतिशत है, जो डिजिटल माध्यम से लैंगिक अंतर को पाटने की तत्काल आवश्यकता को दशार्ता है। डिजिटल पहुँच में इस लैंगिक अंतर और डिजिटल माध्यम से ज्ञान के प्रसार की चुनौतियों का समाधान करते हुए, तीसरा विषय "डिजिटल युग में लैंगिक और पहुँच के संदर्भ में ज्ञान संचरण" पर जोर देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाषा-समावेशी बौद्ध संसाधनों, मोबाइल माइंडफुलनेस ऐप्स और वर्चुअल रिट्रीट जैसे नवाचारों के माध्यम से, बुद्ध की आध्यात्मिक शिक्षाओं के संरक्षण की चुनौतियों का समाधान करती है।

अंतिम विषय वस्तु में समकालीन आवश्यकताओं के लिए ऐतिहासिक ज्ञान को जोड़ने और शिक्षाओं को सुलभ बनाने में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। शैक्षणिक संस्थान इन शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता बनाए रखने में प्रमुख संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, अंतिम विषय "ज्ञान के संरक्षक के रूप में बौद्ध शैक्षणिक संस्थानों और संघ की स्थितिः भविष्य के लिए सामुदायिक शिक्षा और संरक्षण" पर प्रकाश डालेगा।

भारत भर के युवा प्रतिभाओं का एक उत्कृष्ट समूह उपरोक्त विषय पर प्रस्तुति देने के लिए एक साथ आ रहा है। इसलिए, तीसरा आईसीवाईबीएस, धम्म संरक्षकों की अगली पीढ़ी के पोषण और समकालीन संदर्भों में बुद्ध धम्म के शाश्वत मूल्यों पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। अशोक की विरासत, गुरु-शिष्य परंपरा के ज्ञान, डिजिटल युग में समावेशिता की आवश्यकता और शैक्षणिक एवं मठीय संस्थानों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बौद्ध ज्ञान का प्रसार 21वीं सदी और उसके बाद भी जीवंत, सुलभ और प्रासंगिक बना रहे।

वियतनाम, रूस, कंबोडिया और म्यांमार जैसे कई देशों के विद्वान, जो भारत में रहते हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, तथा बौद्ध अध्ययन पृष्ठभूमि वाले युवा शिक्षाविदों द्वारा शोधपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

आईजीएनसीए ने अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देते हुए पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया

आईजीएनसीए ने भारत के विज्ञान और संस्कृति के एकीकृत मंच के उपलक्ष्य में बीएसआईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त ट्रस्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बीएसआईपी), लखनऊ के साथ आईजीएनसीए, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित ग्यारह पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. महेश जी. ठक्कर थे। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी, डीन (अकादमिक) प्रो. प्रतापानंद झा, अकादमिक इकाई के प्रभारी प्रो. अरुण भारद्वाज और संबंधित प्रभागों के अन्य प्रमुख और डीन भी उपस्थित थे।

यह समझौता ज्ञापन देश में विज्ञान और संस्कृति को एक एकीकृत मंच पर लाने की अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य देश की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने प्रदर्शित करना है। इस अवसर पर, आईजीएनसीए द्वारा संचालित ग्यारह पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक सूचना विज्ञान से लेकर भारतीय साहित्य तक के क्षेत्र शामिल थे। इसका उद्देश्य समकालीन शिक्षा में पारंपरिक ज्ञान को समाहित करना था। कुशल पेशेवरों को विकसित करने के लिए तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। इससे शिक्षार्थियों, विशेषज्ञों और जीवंत परंपराओं के बीच सार्थक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।

डॉ. सच्चिदानंद जोशी और प्रो. महेश जी. ठक्कर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईजीएनसीए के संरक्षण प्रभाग के प्रमुख एवं प्रोफेसर डॉ. अचल पंड्या और बीएसआईपी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शिल्पा पांडे इस सहयोग के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगी। आईजीएनसीए और बीएसआईपी के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतःविषय

अनुसंधान, संयुक्त आयोजनों और साझा विशेषज्ञता के माध्यम से विज्ञान और संस्कृति को एकीकृत करना है। यह डिजिटलीकरण, शिक्षा और समुद्री इतिहास में जलवायु परिवर्तन पर प्रोजेक्ट मौसम के समर्थन पर केंद्रित है। सहयोग में अनुसंधान, प्रलेखन, संरक्षण, संग्रहालय विकास, क्षेत्रीय कार्य, दृश्य-श्रव्य अभिलेख, संयुक्त प्रकाशन, और संरक्षण एवं विरासत प्रबंधन में प्रशिक्षण के साथ-साथ जन-पहुंच शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की विरासत को संरक्षित, व्याख्यायित और प्रस्तुत करना है।

इस अवसर पर, प्रो. महेश जी. खट्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और बीएसआईपी के बीच सहयोग विज्ञान, कला और संस्कृति को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पहल से अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ेगी और युवा पीढ़ी प्रेरित होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल हमारे इतिहास और विरासत को समझने के लिए है, बल्कि भविष्य के लिए उनके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने आगे बताया कि यह विज्ञान, कला और संस्कृति को एक मंच पर लाने के लिए आईजीएनसीए के साथ एक संयुक्त प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में और अधिक प्रदर्शनियां, शोध और प्रकाशन किए जाने और लोगों को पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जागरूक करने के लिए ही आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

पाक की धमकी यदि भारत ने डैम बनाया तो मिसाइल से उसे उड़ा देंगे

अमेरिकन सिटी फ्लोरिडा से पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी भरा बयान दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए संघर्ष के तीन महीने बाद अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान सामने आया है। मुनीर ने दावा किया है कि मई में हुए संघर्ष में पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने का दावा करता है लेकिन ऐसा वुछ नहीं है। आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब शनिवार और रविवार को ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय थल सेना और वायु सेना प्रमुखों के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। पहले बता दें कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमले के जवाब में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर किसी भी पारंपरिक मिशन से अलग था। शनिवार को भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दावा किया था कि मई में हुए संघर्ष के दौरान भारत ने छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। हालांकि उसी रोज पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान जारी कर इसका खंडन किया। 10 मई को संघर्ष विराम पर सहमति बनने के बाद गोलीबारी थम गई थी। उस समय पाकिस्तान ने भारत के पांच लड़ावू विमान गिराने का दावा किया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। फ्लोरिडा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक निजी कार्यक्रम में दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के भेदभाव पूर्ण और दोहरे व्यवहार वाली नीतियों के खिलाफ एक सफल वूटनीतिक युद्ध लड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में शामिल है और इस संबंध में उन्होंने कनाडा में एक सिख नेता की हत्या, कतर में आठ नौसेना अधिकारियों का मामला और वुलभूषण जाधव जैसी घटनाओं का उदाहरण दिया। गौरतलब है कि भारत पहले ही इन सभी आरोपों का खंडन कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद आभारी है। जिनके राजनीतिक नेतृत्व में न केवल भारत पाक युद्ध को रोका बल्कि दुनिया में कई युद्धों को भी रोका। फील्ड मार्शल मुनीर ने अपने भाषण में कश्मीर को एक अधूरा एजेंडा बताया।

आसिम मुनीर यहीं नहीं रूके उन्होंने भारत को खुली धमकी दे डाली।

मुनीर ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया तो हम मिसाइल से उसे उड़ा देंगे। मुनीर ने कहा, हम भारत के सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो हम मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर यह गीदड़ भभकी देने से भी नहीं चूके कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर का यह बयान इस लिहाज से सनसनीखेज है कि पहली बार अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने जिस तरह खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस पर अपनी-अपनी राय हो सकती है। बहरहाल इससे एक बात तो साबित होती ही है कि पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति होना केवल भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यह दुखद है कि मुनीर का यह बयान अमेरिका की धरती से आया है। यह पहली बार है जब किसी ने अमेरिकी धरती से किसी तीसरे देश के लिए इस तरह के धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह भी पहली बार है जब किसी सेना प्रमुख ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। मुनीर के बयान का भारतीय विदेश मंत्रालय ने सही जवाब दिया है कि जिस देश में सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हो, वहां परमाणु कमांड और वंट्रोल की विश्वसनीयता पर संदेह होना स्वाभाविक है।

गुजरात को मिली एक और पशु चिकित्सा एवं पशुपालन कॉलेज की सौगात

कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिम्मतनगर में कामधेनु वेटरनरी कॉलेज को मिली स्वीकृति, 80 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

23 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक कैम्पस, उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ ही विद्यार्थियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध

तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए

गांधीनगर, 13 अगस्त : गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा और अंतिम छोर के लोगों की सुख-समृद्धि के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में, राज्य के विद्यार्थियों के उज्ज्वल करियर के लिए एक और नई सुविधा की सौगात दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा गुजरात के हिम्मतनगर में एक नया पशु चिकित्सा एवं पशुपालन कॉलेज शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इस कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से 80 सीटों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी।

उल्लेखनीय है कि कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिम्मतनगर में नया कामधेनु वेटरनरी कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा

गया था। इस विषय में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) द्वारा निरीक्षण और उचित समीक्षा के बाद इस वर्ष से यह कॉलेज शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

कॉलेज प्रवेश और पाठ्यक्रम

वेटरनरी चिकित्सा की पढ़ाई के लिए आणंद, नवसारी, जूनागढ़ और दांतीवाड़ा के बाद यह राज्य में पांचवां कॉलेज है। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद इस कॉलेज में नीट की परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थी इस कॉलेज में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस (बीवीएससी) और एनिमल हसबेंडरी (एएच) डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जिसमें 01 प्रिंसिपल, 04 प्रोफेसर, 07 एसोसिएट प्रोफेसर, 34 असिस्टेंट प्रोफेसर और 23 गैर-शिक्षण स्टाफ शामिल हैं।

अत्याधुनिक कैम्पस और कम फीस पर उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधा

इस कॉलेज के शुरू होने से अब राज्य के विद्यार्थियों को एक और बेहतर कॉलेज में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस कॉलेज का कैम्पस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। विद्यार्थियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार कम फीस पर उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ ही आवास की सुविधा भी उपलब्ध है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में पशु स्वास्थ्य मेलों की शुरूआत की गई थी। गुजरात देश का ऐसा राज्य है; जहाँ पशुधन के लिए हेल्थकार्ड, पशु स्वास्थ्य मेलों तथा पशुओं के मोतियाविंद के ऑपरेशन की सुविधाएँ भी विकसित की गई हैं। इस अभियान को आगे ले जाने में यह कॉलेज आगामी समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गुजरात : 22 बड़ी इकाइयों के आवेदन मंजूर, अनुमानित 4136 से अधिक रोजगार का सृजन

राज्य में कुल 1478 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश वाली 22 बड़ी इकाइयों के आवेदन मंजूर, अनुमानित 4136 से अधिक रोजगार का सृजन

राज्य में 'इंसेंटिव टु इंडस्ट्रीज' योजना अंतर्गत अनुमानित 1.48 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ 1.65 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन : उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत

गांधीनगर, 13 अगस्त : गांधीनगर में उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत की अध्यक्षता में उद्योगों को फाइनल एलिजिबिलिटी प्रमाणपत्र देने संबंधी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 1478.71 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश वाली 22 बड़ी इकाइयों के आवेदन मंजूर किए गए, जिससे राज्य में अनुमानित 4136 नए रोजगार का सृजन हुआ है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सहित समग्र देश में एक उद्योगानुकूल इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है, जिससे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में 'इंसेंटिव टु इंडस्ट्रीज' योजना अंतर्गत 148336.35 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश तथा 1.65 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है, जिसके फलस्वरूप एमएसएमई सेक्टर के लघु एवं मध्यम स्तरीय आनुषांगिक उद्योगों को अधिक वेग मिला है।

श्री राजपूत ने आगे कहा कि आज मंजूर किए गए आवेदनों में अहमदाबाद जिले में मेटल, पेपर,

फूड-एग्रो, सिमेंट-कंक्रीट सेक्टर में 383.91 करोड़ रुपए, कच्छ में मेटल सेक्टर में 227.77 करोड़ रुपए, भरूच में केमिकल एवं सिरामिक सेक्टर में 218.88 करोड़ रुपए, मेहसाणा में पेपर सेक्टर में 55.23 करोड़ रुपए, मोरबी में सिरामिक, मेटल, पेपर, टेक्सटाइल सेक्टर में 167.70 करोड़ रुपए, राजकोट में मेटल सेक्टर में 36.22 करोड़ रुपए, वलसाड में केमिकल, प्लास्टिक तथा पेपर सेक्टर में 359.47 करोड़ रुपए तथा सुरेन्द्रनगर जिले में पेपर सेक्टर में 29.53 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है, जो राज्य में उद्योगों को अधिकाधिक सक्षम बनाने तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से गुजरात में रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि गुजरात को व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक विकास का प्रकाशस्तंभ बनाने के विजन के साथ राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2015 अंतर्गत 'इंसेंटिव टु इंडस्ट्रीज' योजना लागू की गई है। गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में अग्रसर करने, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने तथा नए प्रोजेक्ट्स में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ यह योजना लागू की गई है। राज्य में आने वाले उद्योगों को नेट एसजीएसटी सहायता देने संबंधी इस योजना के माध्यम से गुजरात केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में निवेश का सबसे आकर्षक स्थल बना है, जिसे बड़े उद्योगों द्वारा अच्छा-खासा समर्थन मिला है।

इस बैठक में उद्योग एवं खान विभाग की प्रधान सचिव सुश्री ममता वर्मा, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप सहित उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

पीएनबी ने उन्नत डीलर वित्तपोषण समाधानों के लिए मारुति सुजुकी के साथ साझेदारी की

13 अगस्त 2025: भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत समस्त भारत में मारुति सुजुकी के डीलर नेटवर्क के लिए व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग समाधान प्रदान किए जाएँगे। यह रणनीतिक साझेदारी देश भर के ऑटोमोबाइल डीलरों की वर्किंग कैपिटल तक पहुँच बढ़ाने और उनकी परिचालन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किए गए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद प्रदान करेगी।

पीएनबी डिजिटल माध्यम से ₹25 करोड़ तक की ऋण सुविधाओं हेतु स्वीकृति प्रदान कर रहा है। यह साझेदारी मारुति सुजुकी इंडिया

लिमिटेड के डीलरों को बिना किसी परेशानी के ऋण सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को सीएमएस (नकद प्रबंधन प्रणाली) सेवाएँ भी प्रदान करेगी।

इस समझौता ज्ञापन पर पीएनबी के एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र, वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी, मार्केटिंग एवं सेल्स श्री पार्थो बनर्जी, कार्यपालक उपाध्यक्ष, मार्केटिंग एवं सेल्स श्री त्सुयोशी ताकेशिता और मारुति सुजुकी फाइनेंस एवं ड्राइविंग स्कूल के उपाध्यक्ष श्री विशाल शर्मा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इस साझेदारी पर अपने व्याख्यान में, पीएनबी के एमडी एवं सीईओ श्री अशोक चंद्र ने कहा कि "मारुति सुजुकी के साथ यह साझेदारी नवोन्मेषी वित्तीय समाधानों के माध्यम से भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पीएनबी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारे विशेष रूप से तैयार किए गए इन्वेंट्री फंडिंग उत्पाद डीलरों को बेहतर तरलता, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और त्वरित अनुमोदन तंत्र प्रदान करेंगे। हमें विश्वास है कि यह सहयोग ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और साथ ही मोबिलिटी क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय बैंकिंग भागीदार के रूप में पीएनबी की स्थिति को और सशक्त करेगा। यह साझेदारी रणनीतिक उद्योग सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।"

इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी, मार्केटिंग एवं सेल्स, श्री पार्थो बनर्जी ने कहा, "हमारे डीलर पार्टनर हमारी सफलता के अभिन्न अंग हैं। पंजाब नैशनल बैंक के साथ यह साझेदारी बढ़ती बाजार माँगों को पूरा करने के लिए मजबूत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम आगे है। हमारा मानना है कि यह पहल उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगी और समग्र ग्राहक संतुष्टि में योगदान देगी। यह साझेदारी ऑटोमोटिव इकोसिस्टम को समर्थन देने और भारत के मोबिलिटी सेक्टर के विकास में योगदान देने के मारुति सुजुकी और पंजाब नैशनल बैंक के साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है।"

इनमोबी ने लखनऊ में किया प्रवेश; विश्वस्तरीय बाजारों के लिए डीप-टेक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए खोला नया कार्यालय

लखनऊ का नया कार्यालय जनरेटिव एआई, एमएलओ पीएस, ऑटोमेशन एवं एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर में आधुनिक तकनीकों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्तर भारत में टेक हब की भूमिका निभाएगा।

यह पहल उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो लखनऊ को उभरते एआई इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करेगा।

लखनऊ, 13 अगस्त, 2025: एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर InMOBI ने आज लखनऊ में नए टेक्नोलॉजी सेंटर का लॉन्च किया। इस लॉन्च के साथ यह शहर कंपनी के ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क में शामिल हो गया है।

InMOBI, जो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में मशहूर है, लखनऊ में प्रवेश करने वाली कुछ पहली ग्लोबल डीप-टेक कंपनियों में से एक है। यह InMOBI के मिशन के अनुसार भारत के महानगरों के दायरे से बढ़कर छोटे शहरों में इनोवेशन को विकेंद्रीकृत करने, प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा एआई एवं डीप-टेक में भारत के ग्लोबल लीडरशिप को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ का यह टेक सेंटर आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग ऑपरेशन्स, ऑटोमेशन और बड़े पैमाने पर एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास सहित आधुनिक तकनीकों में इनोवेशन्स को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाएगा।

InMOBI ने आने वाले सालों में इस सेंटर में 500 डीप-टेक इंजीनियर, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट और डेटा साइंस प्रोफेशनल्स भर्ती करने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि इस निवेश से क्षेत्र में 3000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी- जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश को 2029 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

'InMOBI में हमारा मानना है कि महान प्रतिभा किसी भोगौलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती, यह

मानसिकता, महत्वाकांक्षा एवं अवसर से प्रेरित होती है,' मोहित सक्सेना, सह-संस्थापक एवं ग्रुप सीटीओ InMOBI और ग्लांस ने कहा। "पिछले दो दशकों में हमने बैंगलोर और सैन फ्रांसिस्को (दो विश्वस्तर पर विख्यात टेक हब) के बाहर विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग टीमें बनाई हैं। अब हम लखनऊ को भी इस लीग में शामिल कर रहे हैं। यह पारम्परिक महानगरों के दायरे से बढ़कर वाइब्रेन्ट डीप-टेक सिस्टम बनाने की दिशा में एक नई शुरूआत है। उत्तर प्रदेश की स्थानीय प्रतिभा में निवेश, अकादमिक जगत के सहयोग और विश्वस्तरीय बाजारों के लिए आधुनिक उत्पादों के निर्माण के साथ हम भारत के इनोवेशन मानचित्र को नया आकार दे रहे हैं- यह केवल एक शुरूआत है।' सक्सेना ने कहा।

लखनऊ में भारत की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रतिभा है । कई प्रतिष्ठित संस्थान इसी क्षेत्र के आस-पास हैं, जैसे - आईआईटी कानपुर, आईआईआईटी लखनऊ, आईआईएम लखनऊ और एमएनएनआईटी अलाहाबाद। ऐसे में यह क्षेत्र फ्यूचर-रैडी टेक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हब है। InMOBI में व्यवहारिक प्रोडक्ट प्रशिक्षण प्रदान करने तथा वास्तविक दुनिया की जरूरतों के अनुरूप इंटर्नशिप एवं अपस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए स्थानीय यूनिवर्सिटियों एवं शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी की योजना बनाई है । इन प्रयासों से अकादमिक जगत एवं इनोवेशन के बीच के अंतर को दूर करने में मदद मिलेगी।

'लखनऊ में हमारी मौजूदगी इस अवधारणा पर आधारित है कि प्रतिभा हर स्थान पर मौजूद है- हमारी जिम्मेदारी इसे सही दिशा प्रदान करना है, शेफाली राय, चीफ 'मन रिसोर्सेज ऑफिसर, InMOBI और ग्लांस ने कहा। हमारा उद्देश्य ऐसे कार्यस्थल का निर्माण करना है जहां लोगों को आधुनिक विश्वस्तरीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए अपना शहर न छोड़ना पडे। क्लटडइक के बेहतरीन परफोर्मेन्स, समावेशी मूल्यों एवं डीप-टेक अवसरों के साथ हम उभरती प्रतिभा को उनके अपने क्षेत्र में विश्वस्तरीय करियर बनाने के लिए तैयार करना चाहते हैं।'

InMOBI का नया लखनऊ कार्यालय कंपनी की इनोवेशन योजनाओं तथा इसी साल एआई के लिए की गई 200 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता का एक भाग है, जिसमें ग्लांस एआई का लॉन्च भी शामिल है। ग्लांस एआई एक रेवोल्युशनरी एआई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में खरीददारी के तरीके को बदल रहा है। अपने आर एण्ड डी फुटप्रिंट को विकेंद्रीकृत करके कंपनी पारम्परिक शहरी केन्द्रों के दायरे से बढ़कर इनोवेशन, प्रतिभा के समावेशी विकास एवं स्थायी टेक सिस्टम के विकास को बढ़ावा देना चाहती है।

ट्राई ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर ट्राई की 17.02.2025 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के 03.07.2025 के बैक-रेफरेंस का जवाब दिया

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर ट्राई की 17.02.2025 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।

इससे पहले, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत दिनांक 26.07.2024 के एक संदर्भ के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकरण के लिए शुल्क या प्रभार सहित नियम और शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, दिनांक 17.10.2024 के एक अधिशेष पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 3(1)(बी) के तहत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण पर विचार करने का अनुरोध किया था।

हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, ट्राई ने 17.02.2025 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर सिफारिशें दूरसंचार विभाग को प्रदान कीं।

इसके बाद, 03.07.2025 को, दूरसंचार विभाग ने ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के तहत एक बैक-रेफरेंस भेजा और ट्राई से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर कुछ सिफारिशों के संबंध में पुनर्विचारित सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया, जहां सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या उनमें संशोधन की आवश्यकता है।

ट्राई की सिफारिशों पर सरकार के प्रथम दृष्टया विचारों का विश्लेषण करने के बाद, ट्राई ने दूरसंचार विभाग को बैक-रेफरेंस पर अपना जवाब भेज दिया है। बैक-रेफरेंस पर ट्राई का जवाब ट्राई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

किसी भी स्पष्टीकरण या विवरण के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

नेटवर्क योजना समूह की 98वीं बैठक में रेलवे, सड़क, लॉजिस्टिक्स और वस्त्र क्षेत्र की 7 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन किया गया

(जीएनएस)।

नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक सड़क/राजमार्ग परियोजना, एक मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी), तीन रेल परियोजनाएं और पीएम मित्र योजना के अंतर्गत दो टेक्सटाइल पार्क सहित सात परियोजनाओं का आकलन किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये परियोजनाएं एकीकृत मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक एवं सामाजिक केंद्रों के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी और इंटर-मॉडल समन्वय के प्रधानमंत्री गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, यात्रा समय में कमी तथा विभिन्न क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

रेल मंत्रालय

बख्तियारपुर और फतुहा (बिहार) के बीच तीसरी और चौथी लाइन

रेल मंत्रालय ने बिहार के पटना ज़िले में बख्तियारपुर और फतुहा के बीच 24.156 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह खंड किऊल-पटना-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कॉरिडोर (लगभग 390 किलोमीटर) पर एक बहु-ट्रैकिंग पहल का हिस्सा है।

यह परियोजना क्षेत्रीय गतिशीलता, माल ढुलाई क्षमता और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करेगी, जिससे अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट (बाढ़), कैरिज रिपेयर वर्कशॉप (हरनौत) और एसजेवीएन पावर प्लांट (चौसा) सहित प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ ऑटोमोटिव, संगमरमर, पत्थर, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम और वस्त्र उद्योग के एसएमई को लाभ होगा।

उपजाऊ कृषि क्षेत्र से होकर गुजरने वाली इस रेल लाइन से किसानों की बाजार तक पहुंच बेहतर होगी और पटना, राजगीर, बोधगया, नालंदा तथा बिहार शरीफ के पर्यटन स्थलों तक पर्यटन संपर्क बढ़ेगा। इससे यात्री क्षमता बढ़ेगी, भीड़भाड़ कम होगी और बिहार तथा आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान मिलेगा।

शहीद स्मारक पर 79 मोमबत्ती जलाकर अमर शहीदों को दी गयी श्रद्धांजलि

भारत माता की जय,वन्देमातरम के नारों से गूंजा शहीद स्मारक
शहीद परिवारों को किया गया सम्मानित
जश्न ए आजादी ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन द्वारा किया गया आयोजन

लखनऊ। जश्न ए आजादी ट्रस्ट एवं उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन द्वारा देश की आजादी के लिए अपने प्राण गवानें वाले वीर शहीदों की याद में "एक शाम वीर शहीदों के नाम" कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक स्थल पर किया गया।

कार्यक्रम में अमर शहीदों की याद में 79 मोमबत्ती और दीप जलाकर एवम पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।

इस अवसर पर सर्व समाज के प्रतिनिधि और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के परिजन उपस्थित थे।

कार्यक्रम में पी.ए.सी. बैंड द्वारा देश भक्ति पर तराने पेश किए गये।

भारत माता की जय,वन्देमातरम के नारों से पूरा शहीद स्मारक गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के लोगो ने कारगिल पार्क में वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्यसभा सदस्य डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि आजादी के महापर्व में हम दुनिया में विकसित भारत के रुप में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं।

इस अवसर पर जश्न ए आजादी ट्रस्ट के अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा ने कहा कि खुशी के इन पलों में हम अपने वतन की कुबार्नी देने वाले क्रांतिकारियों को कभी ना भूलें।15 अगस्त और 26 जनवरी देश का सबसे बड़े त्योहार हैं।

कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का जुबैर अहमद और अब्दुल वहीद ने तिरंगा पट्टी पहनाकर स्वागत किया।

आयोजन में जश्न ए आजादी ट्रस्ट के अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा,महामंत्री निगहत खान,चेयर पर्सन रजिया नवाज,कोषाध्यक्ष वामिक खान,मीडिया प्रभारी और संस्थापक सदस्य अब्दुल वहीद,जुबैर अहमद,मुर्तजा अली,सुशील दुबे,इमरान कुरेशी,नजम अहसन, अनीस अंसारी,कुदरत उल्ला खान,महेश दीक्षित, वफा अब्बास,अभय अग्रवाल,तौसीफ हुसैन,डॉ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी,इंतजार आब्दी बॉबी,परवेज अख्तर, इंसराम अली,डॉ राधेश्याम यादव,मो सैफ,जमील मालिक,आमिर मुख्तार,आफाक मंसूरी,साकेत शर्मा,अहसन रईस,योग गुरु के. डी. मिश्रा,शहाबुद्दीन कुरैशी,रहनुमा कुरैशी,अवधेश सोनकर, अमरजीत, भानु प्रताप सिंह,आरिफ मुकीम, हिमांशु पाण्डेय,क्टर आर.एस.यादव,

कमर अली सलाहुदीन सिद्दीकी शीबू सहित बड़ी संख्या में ट्रस्ट के कार्यकर्ता और आम नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्तिथ रहे।सांय 7:30 बजे राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

'द्वितीयक इस्पात उद्योगों के मुद्दे' पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आज कार्यशाला का आयोजन

(जीएनएस)।

इस्पात मंत्रालय ने द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श हेतु आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "द्वितीयक इस्पात उद्योगों के मुद्दे" पर एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रमुख उद्योग संघों - मैटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई), स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (एसआईएमए), ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन (एआईआईएफए), छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (सीजीएसआईएमए), और पेलेट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएआई) के प्रतिनिधियों के साथ- साथ द्वितीयक इस्पात उद्योगों (एसएसआई) के इस्पात उत्पादक, नीति निमार्ता, विशेषज्ञ और उद्योग भागीदार भी शामिल हुए।

कार्यशाला का उद्घाटन माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने किया। उन्होंने इस क्षेत्र की औद्योगिक क्षेत्रीयकरण की रीढ़ के रूप में भूमिका पर जोर दिया, जो रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने 2047 तक 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य को दोहराया और निम्न- कार्बन इस्पात में विश्व स्तर पर अग्रणी बनने की भारत की महत्वाकांक्षा पर प्रकाश डाला। भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) के अंतर्गत इस्पात सहयोग पोर्टल और हरित इस्पात वर्गीकरण जैसी प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला गया।

इस्पात मंत्रालय में सचिव, श्री संदीप पौंड्रिक ने वैश्विक गिरावट के बीच भारत में इस्पात उत्पादन में 12% से अधिक की मजबूत वृद्धि पर प्रकाश डाला और बताया कि प्रति व्यक्ति खपत 100 किलोग्राम से अधिक हो गई। उन्होंने बताया कि 47% उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र से आता है। उन्होंने अनुसंधान एवं विकास, कच्चे माल की सतत आपूर्ति और रसद सुविधा के लिए मंत्रालय के सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अध्ययनों से पता चलता है कि अगले पाँच वर्षों में हाइड्रोजन की लागत घटकर 2.5 डॉलर प्रति किलोग्राम रह जाने की संभावना है, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन को अपनाने का आग्रह किया जा सके।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संघों द्वारा उद्योग जगत की प्रमुख चिंताओं जैसे- कच्चे माल की आपूर्ति, रसद संबंधी अड़चनें, अस्थिर मूल्य निर्धारण और बिजली शुल्क संबंधी मुद्दे पर चर्चा की गई। मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सतत इस्पात मिशन (एनएमएसएस) पर एक सत्र भी आयोजित किया गया और उद्योगों के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई।

अन्य सत्रों में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति, द्वितीयक इस्पात उद्योग (एसएसआई) के आधारभूत कार्बन उत्सर्जन और एसएसआई के लिए अनुसंधान एवं विकास पहलों पर चर्चा की गई।

भारतीय इस्पात क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में, तीन इस्पात कंपनियों को ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के उनके प्रयासों के लिए पहला ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर विचार विमर्श सत्रः ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हितधारकों के दृष्टिकोणों का संरेखण

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आज डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र ने सरकारी, उद्योगों एवं अकादमी के हितधारकों को एक साथ मिलकर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जो आगामी पूर्ण एएसएसएसई में सर्वेक्षण पद्धति और सर्वेक्षण उपकरणों की परिशुद्धता में सुधार लाने की सुविधा प्रदान करता है जो कि पायलट अध्ययन के माध्यम से प्राप्त अनुभव पर आधारित है।

इस सत्र में विविध क्षेत्रों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और जीवंत चचाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिनमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए), नीति आयोग, आरबीआई, विश्व बैंक, तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) के विशेषज्ञ, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, उद्योग संघ और व्यापार निकाय आदि शामिल हैं।

विचार विमर्श सत्र की अध्यक्षता डॉ. सौरभ गर्ग, आईएएस, सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने की और इसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति देखी गई जिनमें प्रमुख मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग संघों के अन्य अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों सहित डॉ. राकेश मोहन, सदस्य, ईएसी-पीएम, डॉ. राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉ. उमाकांत दाश, कुलपति, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, डॉ. बी. एन. गोल्डर, अध्यक्ष, टीएजी, डॉ. अमीर उल्लाह खान, अर्थशास्त्री और प्रोफेसर, आईएसपीपी, डॉ. तौकीर अहमद, प्रोफेसर, आईएएसआरआई, सुश्री गीता सिंह राठौर, महानिदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस), श्री एन.के.संतोषी, महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी) भी शामिल हुए।

डॉ. सौरभ गर्ग, सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने नीतिगत आवश्यकताओं के अनुसार नए सर्वेक्षण शुरू करने और कुछ मौजूदा सर्वेक्षणों, जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) और असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के परिणामों की आवृत्ति बढ़ाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया। सेवाओं के क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमुख आर्थिक सूचकांकों जैसे मूल्य संवर्धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात एवं रोजगार में रेखांकित करते हुए, डॉ. गर्ग ने वार्षिक सेवाओं के क्षेत्र उद्यमों के सर्वेक्षण (एएसएसएसई) की शुरूआत के पीछे के औचित्य को स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ सार्थक सहयोग सर्वेक्षण की डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने उद्योग निकायों एवं व्यापार संघों से सटीक तथा समय पर आंकड़े उपलब्ध कराकर अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया जो सर्वेक्षण की सफलता और इसके निष्कर्षों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा।

डॉ. राकेश मोहन, सदस्य, ईएसी-पीएम ने सेवा उद्योग के विभिन्न उप-क्षेत्रों के बारे में बताया जिनकी अर्थव्यवस्था में बढ़ती महत्ता के कारण सर्वेक्षण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉ. राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स ने अपने संबोधन में एनएसएस को देश की सेवा में 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने इस नए सर्वेक्षण को शुरू करने के लिए जीएसटीएन डेटा का लाभ उठाने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भी सराहना की जिसमें एएसयूएसई के साथ मिलकर सेवा क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है। विश्व बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री थॉमस डेनियलविट्ज ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उल्लेख करते हुए एक व्यापक व्यवसाय रजिस्टर (बीआर) बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) और सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) जैसे सर्वेक्षणों के लिए एक मजबूत संरचना के रूप में कार्य करेगा।

तकनीकी सत्र की शुरूआत में, सुश्री गीता सिंह राठौर, महानिदेशक (एनएसएस), एमओएसपीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के महत्व और हितधारकों के साथ सहयोग में सर्वेक्षण पद्धति को आकार देने में विचार विमर्श सत्र के महत्व को पुनः रेखांकित किया।

तकनीकी सत्र में एएसएसएसई का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इसके उद्देश्य, क्षेत्रीय कवरेज, प्रस्तावित नमूनाकरण संरचना, हाल ही में किए गए पायलट अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष एवं सेवा उत्पादन सूचकांक तैयार करने में एएसएसएसई आंकड़ों की उपयोगिता शामिल थी। इस सत्र में वैश्विक स्तर पर किए गए इसी तरह के सर्वेक्षण अभ्यासों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अवलोकन भी शामिल था।

तकनीकी सत्र के बाद एक खुली चर्चा आयोजित की गई जिसमें विभिन्न हितधारक मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचारों का साझा किया तथा सर्वेक्षण से अपनी डेटा आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला।

विचार विमर्श सत्र से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष

एएसएसएसई के लिए नमूना फ्रेम के रूप में जीएसटीएन डेटाबेस का समर्थन

प्रमुख हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण अनुसूची का संशोधन

सर्वेक्षण को हितधारकों की आवश्यकता के अनुरूप बनाना

सर्वेक्षण प्रतिक्रिया दर बढ़ाने में उद्योग संघों की भागीदारी

नावेद अहमद, समाजवादी पार्टी का नया सितारा, जो युवा जोश से बदल रहा है सियासत का रंग, युवा शक्ति का सियासी सूरज, नावेद अहमद

लखनऊ की सियासी गलियों में एक नया नाम गूंज रहा है, नावेद अहमद, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी नजर भविष्य पर है और उनका दिल युवा जोश के साथ धड़कता है। लखनऊ की 174-मध्य विधानसभा के इस कर्मठ युवा नेता को समाजवादी लोहिया वाहिनी, उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर अखिलेश ने न केवल एक जिम्मेदारी सौंपी है, बल्कि एक नई सियासी कहानी का आगाज किया है। यह कहानी है सपनों की, जुनून की, और उस युवा शक्ति की, जो समाजवादी विचारधारा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को बेताब है।

नावेद अहमद कोई साधारण नाम नहीं है। लखनऊ की गलियों में उनकी मेहनत, जमीनी स्तर पर उनकी पकड़, और समाजवादी विचारधारा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने नावेद को चुना, क्योंकि वे जानते हैं कि सियासत का भविष्य वही लिखेगा, जिसके पास जुनून है, जोश है, और जनता के दुख-दर्द को समझने का जज्बा है। नावेद की यह नियुक्ति सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक संदेश है, समाजवादी पार्टी अब युवा कंधों पर भरोसा कर रही है, जो बूथ से लेकर बड़े मंच तक पार्टी का परचम लहराएंगे।

लखनऊ-मध्य विधानसभा में नावेद का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनकी सक्रियता और कार्यकताओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक ऐसा नेता बनाया है, जो जनता के दिलों में बसता है। अब, समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में, नावेद की जिम्मेदारी है कि वे बूथ स्तर पर पार्टी की नींव को और मजबूत करें। यह कोई आसान काम नहीं, लेकिन नावेद के हौसले और उनकी युवा ऊर्जा को देखकर लगता है कि वे न केवल इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, बल्कि इसे एक मिसाल में बदल देंगे।

जैसे ही नावेद की नियुक्ति की खबर फैली, लखनऊ की सड़कों से लेकर कार्यकताओं के दिलों तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ता इसे एक नए युग की शुरूआत मान रहे हैं। नावेद भाई हमारे लिए प्रेरणा हैं। उनकी मेहनत और नेतृत्व से समाजवादी पार्टी को नई ताकत मिलेगी, एक कार्यकर्ता ने गर्व से कहा। यह उत्साह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए है, जो युवाओं को सियासत की मुख्यधारा में ला रही है।

अखिलेश यादव की सियासत हमेशा से दूरदर्शी रही है। चाहे वह तकनीक का इस्तेमाल हो या युवाओं को मौका देना, वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। नावेद अहमद की नियुक्ति इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रही, बल्कि भविष्य की नींव रख रही है। यह नियुक्ति एक रणनीति है, युवा दिलों को साधने की, उन्हें नेतृत्व देने की, और उन्हें यह एहसास कराने की कि समाजवादी पार्टी उनके सपनों का मंच है।

नावेद जैसे युवा नेताओं के सहारे सपा न केवल संगठन को मजबूत कर रही है, बल्कि आगामी चुनावों के लिए एक ऐसी सेना तैयार कर रही है, जो नई सोच, नई ऊर्जा, और नई उम्मीदों के साथ मैदान में उतरेगी। यह एक ऐसी कहानी है, जो हर युवा के दिल को छू रही है, एक ऐसी कहानी, जो कहती है कि अगर तुममें जुनून है, तो सियासत तुम्हारा इंतजार कर रही है।

नावेद अहमद की यह नई पारी सिर्फ लखनऊ-मध्य तक सीमित नहीं रहेगी। उनकी नियुक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकताओं में नया जोश भरेगी। यह एक ऐसा कदम है, जो न केवल पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करेगा, बल्कि समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में भी मददगार साबित होगा। नावेद का नेतृत्व उस आग की तरह है, जो धीरे-धीरे जलती है, लेकिन एक बार भड़कने पर सब कुछ रौशन कर देती है।

नावेद अहमद की नियुक्ति समाजवादी पार्टी के लिए एक नई सुबह की तरह है। यह एक ऐसा मौका है, जब युवा शक्ति और अनुभवी नेतृत्व का संगम एक नई सियासी क्रांति की नींव रख रहा है। लखनऊ की सड़कों से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक, यह खबर गूंज रही है कि समाजवादी पार्टी अब नई पीढ़ी के साथ नया इतिहास लिखने को तैयार है।

तो आइए, इस नए सितारे का स्वागत करें, जो समाजवादी आकाश में चमकने को तैयार है। नावेद अहमद, तुम्हारा यह सफर न केवल तुम्हारी मेहनत की कहानी है, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीद भी है, जो समाजवादी पार्टी के झंडे तले एक बेहतर कल का सपना देख रहे हैं। चलो, मिलकर इस सियासी रंग को और गहरा करें, क्योंकि समाजवाद का यह कारवां अब रुकने वाला नहीं!

स्वतंत्रता दिवस से पूर्व स्योहारा में तिरंगे का अद्भुत जश्न

(जीएनएस)।

बिजनौर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के तहत बुधवार को नगर पालिका परिषद स्योहारा द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा नगर पालिका कार्यालय से प्रारंभ होकर नवादा चुंगी, शिवाजी मार्केट, रेलवे स्टेशन, स्टेशन चौराहा, थाना चौक, फौवारा चौक नगर आदि प्रमुख मार्गो से होती हुई पुनः नगर पालिका कार्यालय पर संपन्न हुई।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष फैसल वारसी, अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी, व्यापारी मंडल, स्वयंसेवी संस्थाएं, रोटरी क्लब, स्कूली छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट-गाइड, एम क्यू इंटर कॉलेज व आरएसपी इंटर कॉलेज के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से वातावरण गुंजायमान रहा।

नगर पालिका द्वारा आयोजित इस यात्रा में नगर की समस्त वार्ड सभासद, क्षेत्रीय गणमान्य, महिला-पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज की महिमा और इसके सम्मान पर जोर दिया गया। आयोजकों ने जनता से स्वतंत्रता दिवस पर अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को तिरंगे के महत्व और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हर नागरिक में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना और "हर घर तिरंगा" अभियान को सफल बनाना रहा।

पति ने पत्नी पर नीले ड्रम में भरने की धमकी का लगाया आरोप

(जीएनएस)।

बिजनौर।

धामपुर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच गंभीर विवाद का मामला सामने आया है। नहटौर निवासी नदीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने उसे जान से मारकर नीले ड्रम में भरने की धमकी दी है। नदीम का कहना है कि उसकी पत्नी के किसी युवक से संबंध हैं, जिसके साथ मिलकर वह आए दिन उसे डराती-धमकाती है। उसने दावा किया कि कई बार वह पत्नी को युवक के साथ रंगे हाथ पकड़ चुका है। आरोप है कि पत्नी अकेले में प्रेमी को फोन कर घर बुलाती है और नदीम को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।

नदीम ने बताया कि उसकी शादी आठ साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ गए हैं। वहीं, पत्नी ने पति के सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है। उसका कहना है कि नदीम अक्सर उससे मारपीट करता है और बेबुनियाद आरोप लगाकर मानसिक प्रताड़ना देता है। उसने यह भी कहा कि उसे धमकी देने जैसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया है।

पत्नी का आरोप है कि नदीम बिना सबूत कई तरह के आरोप लगाता है और लोगों के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता है। उसने दावा किया कि उसके खिलाफ किसी प्रकार का प्रमाण मौजूद नहीं है।

धामपुर पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि मामला घरेलू विवाद के साथ-साथ गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा हुआ है।

पहाड़ा नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा जारी

(जीएनएस)।

बिजनौर।

उत्तराखंड सीमा से सटे कस्बा बढ़ापुर की पहाड़ा नदी पर पुल निर्माण की मांग लगातार तेज होती जा रही है। बुधवार को दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने नदी किनारे पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल न होने से बरसात के दिनों में आवागमन ठप हो जाता है, जिससे गंभीर हादसे और जान हानि जैसी स्थितियां बन जाती हैं।

गौरतलब है कि दो दिन पहले पहाड़ा नदी में उफान के कारण ग्राम चकउदयचंद निवासी 42 वर्षीय ओमराज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सके और उपचार के अभाव में उनकी मौत हो गई थी। ओमराज की मौत के बाद ग्राम चकउदयचंद, सरदारपुर और बहेड़ी के सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को नदी किनारे पहुंचकर पुल निर्माण की मांग को लेकर घंटों तक हंगामा किया था।

बुधवार को भी बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे एकत्र हुए और पुल निर्माण की मांग दोहराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका आक्रोश कम नहीं हुआ।

इधर, जिला प्रशासन के आदेश पर एनडीआरएफ की 18 सदस्यीय टीम चार बोट के साथ बढ़ापुर पहुंची है, ताकि जरूरत पड़ने पर नदी से प्रभावित ग्रामीणों की मदद की जा सके। हालांकि, बुधवार को नदी का जलस्तर कम होने के कारण टीम को कोई रेस्क्यू कार्य शुरू नहीं करना पड़ा।

इंस्पेक्टर ललित कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ टीम का मुख्य कार्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना होता है। यहां बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन बरसात में जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों को नदी पार करने में कठिनाई होती है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए नदी पर पुल निर्माण ही एकमात्र विकल्प है, जिसे लेकर वे आंदोलन जारी रखेंगे।